JOKERIMAGESNEWS

Praja Foundation report: ‘Corporators asked few questions in BMC meetings to deliver on 2017 poll promises’

2017 के बीएमसी चुनावों में, जबकि राजनीतिक दलों ने 24 घंटे पानी की आपूर्ति, गड्ढों से मुक्त सड़कों, कचरा प्रबंधन और अपने घोषणापत्र में फेरीवालों की नीति के कार्यान्वयन, नागरिक निकाय के आंकड़ों के विश्लेषण सहित कई वादे किए थे। यह दर्शाता है कि नगरसेवकों ने सेवाओं में सुधार के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं।

एनजीओ प्रजा फाउंडेशन के डेटा से पता चलता है कि कुल मिलाकर, बीएमसी को 2017-18 से 2020-21 के बीच विभिन्न नागरिक मुद्दों पर लोगों से 2.66 लाख शिकायतें मिली थीं। हालांकि, सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न बीएमसी समिति की बैठकों में नगरसेवकों द्वारा बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे।

2017-18 से 2020-21 तक गड्ढों से संबंधित 17,908 शिकायतें प्राप्त हुईं। हालांकि, औसतन पार्षदों ने इस मुद्दे पर अपने सवाल का केवल 2 फीसदी ही पूछा। राज शिवसेना अपने घोषणापत्र में मुंबई को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था।

इसी तरह इस दौरान बीएमसी को 34,129 फेरीवालों से संबंधित शिकायतें मिलीं। हालांकि, इस मुद्दे पर नगरसेवकों द्वारा कुल प्रश्नों में से औसतन केवल 6 प्रतिशत ही पूछे गए थे। NS बी जे पीराकांपा और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में फेरीवालों और अन्य रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष जोन का वादा किया था।

बीएमसी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 24 घंटे पानी देने का वादा किया था. हालांकि, शहर के 290 क्षेत्रों में से 204 को 2020 में चार घंटे तक पानी मिला, रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी दलों ने वार्ड स्तर पर कचरा प्रबंधन में सुधार का वादा किया था, लेकिन इस मुद्दे पर बीएमसी को 54,029 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 40 फीसदी कचरा इकट्ठा न करने की थीं.

प्रजा फाउंडेशन के विश्लेषण ने संकेत दिया कि नगरसेवक सड़कों, चौकों और इमारतों के नामकरण और नामकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 से 2020-21 तक, नगरसेवकों ने 8,934 प्रश्न उठाए, जिनमें से 14 प्रतिशत सड़कों, चौकों और इमारतों के नामकरण और नामकरण के संबंध में थे।

“रिपोर्ट में पार्षदों को अपने कार्यकाल के दौरान विचार-विमर्श करते हुए चुनाव से पहले घोषणापत्र में किए गए वादों का उल्लेख करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। गड्ढों, जलापूर्ति, फेरीवालों आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने के वादे किए जाने के बावजूद, उन पर विचार-विमर्श पर्याप्त नहीं है. प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के ने कहा कि गड्ढों से संबंधित मुद्दों पर प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कुल अनुपात केवल 2 प्रतिशत था।

Link: https://jokerimages.in/praja-foundation-report-corporators-asked-few-questions-in-bmc-meetings-to-deliver-on-2017-poll-promises/